



रेस्टो 1021-III-15

मोती लाल S/O मोल इन्द्रास सेना  
वनाप्र वि. शाक-वाचन 212 31/15  
गिरधारी 30 रागशिव लोडिया  
आग-3231 रीवा

रेस्टो 1021-III-15 (3) मध्यप्रदेश राजस्व संहिता 1957 के अंतर्गत  
अधिसूचना राजस्व अधिनियम 1999 के अंतर्गत प्रकट-निगमनी-715(III)99  
उत्तरी अधिसूचना क्रमांक-26/3/15 जमानती निगम-1-5-2015 को सुई

श्रीमानजी

निगमनी प्रकट-715(III)99 उत्तरी अधिसूचना क्रमांक-26/3/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक:-रेस्टो 1021/तीन/15

जिला- उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.05.2015	<p>प्रस्तुत रेस्टो आवेदन के परिपेक्ष में मूल प्रकरण क्रमांक निगम 115-तीन/1999 मोतीलाल/गिरधारी प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह प्रकरण दिनांक 10.02.2001 से इस न्यायालय में प्रचलित है । आवेदक की ओर से याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात् कोई उपस्थित नहीं हुआ था । तब आवेदक को सूचना दी गई । दिनांक 02.01.2006 को प्रकरण सुनवाई के लिये तथा अनावेदक को सूचना एवं रिकार्ड मंगाये जाने के आदेश दिये गये । प्रकरण को ग्राह्य किया गया । दिनांक 09.06.2006 को आदेश पत्रिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में अनावेदक की मृत्यु होने की जानकारी देने पर तब आवेदक अभिभाषक को अनावेदक के वारिसान की जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये, तब से यह प्रकरण निरन्तर आवेदक द्वारा अनावेदक मृतक के वारिसों की जानकारी देने हेतु प्रचलित रहा । अनावेदक के वारिसों की जानकारी नहीं दी गई और निरन्तर समय चाहा गया । दिनांक 20.10.2014 अनावेदक के वारिसों की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये आवेदक अभिभाषक को अन्तिम अवसर दिया गया । परन्तु अभिभाषक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई । आवेदक दिनांक 26.03.2015 को</p>	

91

Reh 1021-10/15-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>— सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहे। इसलिये उनके विरुद्ध अदम पैरवी की कार्यवाही कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया। इस प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानी वर्ष 2001 में प्रस्तुति के पश्चात वर्ष 2006 से दिनांक 26.03.2015 तक अनावेदक वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई और निरन्तर अनावश्यक रूप से लम्बित रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर प्रचलित करने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>अतः आवेदन निरस्त कर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">सदस्य</p>	<p style="text-align: center;"></p>